

SC-ST एक्ट की अलोकप्रयिता एवं वैधानिक औचित्य

चर्चा में क्यों?

20 मार्च को सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य वाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया नरिणय गहन चर्चा का विषय बन गया है। इस नरिणय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत तात्कालिक गरिफ्तारी, अग्रमि जमानत न दिये जाने (CrPC की धारा 438 के अपवाद के रूप में) तथा FIR रजिस्ट्रेशन पर प्रतर्बिध लगा दिया गया है।

मुद्दा क्या है?

- ऐसा कहा जा रहा है कि यह नरिणय इस अधिनियम के प्रभाव को कम करता है तथा इस नरिणय के बाद दलितों पर होने वाले अत्याचार की घटनाओं में वृद्धि होगी, जिस कारण इसका देशव्यापी विरोध हो रहा है।
- वहीं, इसका दूसरा पक्ष यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के नरिणय के द्वारा नरिदोष लोगों की इस अधिनियम के तहत झूठे आरोपों से रक्षा हो सकेगी।
- हालाँकि, यह आवश्यक है कि विधिमिन्य प्रक्रियाओं के आलोक में इस नरिणय की नषिपक्ष समीक्षा की जाए।

वाद विशेष का विश्लेषण

- इस वाद में फार्मिसे के एक सरकारी कॉलेज के स्टोरकीपर द्वारा दो जाँच अफसरों पर वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में उसके “गलत मूल्यांकन” का आरोप लगाया गया है। साथ ही, स्वीकृत प्रदाता प्राधिकारी (नियोजक प्राधिकारी) द्वारा जाँच स्वीकृति न दिये जाने को इस अधिनियम के अतर्गत अत्याचार की संज्ञा दी गई।
- यदि स्वीकृत प्रदाता प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति न देना गलत भी था तो भी इसे अत्याचार की संज्ञा नहीं दी जा सकती थी। इस तरह की घटनाओं से बचने के लिये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि FIR दर्ज करने से पूर्व एक वरिष्ठ समीक्षा आवश्यक है तथा FIR दर्ज के बावजूद, गरिफ्तारी आवश्यक नहीं है।
- यदि अभियुक्त एक सरकारी सेवक है तो नियोजक अधिकारी द्वारा अनुमति ली जानी चाहिये। यदि वह सरकारी सेवक नहीं है तो एसएसपी द्वारा अनुमति ली जानी आवश्यक है।

नरिणय के कानूनी पहलू

- इस नरिणय में अभियुक्त को अग्रमि जमानत न प्रदान किये जाने के प्रावधान को नरिस्त किया गया है। हालाँकि, यदि प्रथम दृष्टया ऐसा पाया जाता है कि इस अधिनियम के तहत अपराध किया गया है तो अग्रमि जमानत प्रदान न किये जाने का प्रावधान लागू होगा।
- सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, जनि मामलों में प्रथम दृष्टया पाया जाता है कि अपराध हुआ है तथा उसकी सुनवाई से पूर्व गरिफ्तारी एवं न्यायिक जाँच आवश्यक है, उन मामलों में इस अधिनियम के प्रभाव को कम नहीं किया गया है।
- न्यायालय द्वारा SC/ST के खिलाफ किये गए अत्याचारों के लिये सजा को कम नहीं किया गया है।
- चूँकि निचले स्तर के पुलिस अफसरों का सरकारी या अन्य प्रकार के दबाव में आने की संभावना अधिक थी इसलिये न्यायालय द्वारा सामान्य नागरिकों के लिये SSP तथा सरकारी सेवकों के मामले में वरिष्ठ अधिकारी की अनुमति को अनिवार्य बनाया गया है।
- गौरतलब है कि NCRB (नेशनल क्राइम रिकार्ड्स ब्यूरो) के आँकड़ों के अनुसार, इस अधिनियम में दर्ज मामलों में से 15% झूठे होते हैं।

न्यायालय द्वारा जारी दिशा-नरिदेश

- ऐसे मामलों में किसी भी नरिदोष को कानूनी प्रताड़ना से बचाने के लिये कोई भी शकियत मलिन पर तत्काल एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। सबसे पहले शकियत की जाँच डीएसपी स्तर के पुलिस अफसर द्वारा की जाएगी।
- न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया है कि यह जाँच पूर्ण रूप से समयबद्ध होनी चाहिये। जाँच किसी भी स्तर में 7 दिनों से अधिक समय तक न चले।
- इन नयिमों का पालन न करने की स्थिति में पुलिस पर अनुशासनात्मक एवं न्यायालय की अवमानना करने के संदर्भ में कार्यवाई की जाएगी।
- अभियुक्त की तत्काल गरिफ्तारी नहीं की जाएगी। सरकारी कर्मचारियों को नयुक्त करने वाली अर्थॉरिटी की लिखित मंजूरी के बाद ही गरिफ्तार हो सकती है और अन्य लोगों को ज़िले के एसएसपी की लिखित मंजूरी के बाद ही गरिफ्तारी किया जा सकेगा।
- इतना ही नहीं, गरिफ्तारी के बाद अभियुक्त की पेशी के समय मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त कारणों पर विचार करने के बाद यह तय किया जाएगा कि क्या अभियुक्त को और अधिक समय के लिये हरिसत रखा जाना चाहिये अथवा नहीं।
- इस मामले में सरकारी कर्मचारी अग्रमि जमानत के लिये भी आवेदन कर सकते हैं। आप को बता दें कि अधिनियम की धारा 18 के तहत अभियुक्त को

नहितारथ

- जनता के दबाव में न आकर न्यायालय द्वारा एक अलोकप्रयि नरिणय लयिा गया ताका भीड़ के न्याय के फलसफे के स्थान पर संवधान के मूलभूत सदिधांतों को कायम रखा जा सके ।
- ऐसा करके अदालत ने नरिदोष वयक्तयिों को कसिी गलत गरिफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की है तथा इससे उनके खलिाफ झूठे मामलों की संख्या में भी कमी आएगी ।
- अफसरों द्वारा जमा की गई जाँच रपिरट को पीड़ति द्वारा साक्ष्य के रूप में उपयोग कयिा जा सकेगा जसिसे उन्हें त्वरति न्याय मलिने में सुवधि होगी ।
- इससे सरकारी सेवक बनिा डर के अपने कर्त्तव्यों का नषिपादन कर सकेंगे ।
- यह सतत् वकिस लक्ष्य 2010 के लक्ष्य 16 की पुष्टकरता है जसिमें न्याय तथा शांतिकी पैरोकारी की गई है ।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/unpopularity-and-legal-justification-of-the-sc-st-act-1>

